

# भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रेटिंग बहाली को लेकर संयुक्त राष्ट्र ले सकता है फैसला

जालंधर, 29 अप्रैल (इंट): संयुक्त राष्ट्र की जेनेवा में होने वाली एक बैठक में भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) के मौजूदा स्टेटस को बरकरार रखने को लेकर फैसला हो सकता है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस सप्ताह जेनेवा में होने वाली एक बैठक में आयोग सरकार की मानवाधिकार प्रक्रियाओं का बचाव करने की तैयारी कर रहा है।

## 2023 में रोक दी गई थी रेटिंग

इस बैठक में इस बात का फैसला होने की उम्मीद है कि भारत का मानवाधिकार आयोग का वर्तमान "ए स्टेटस" बरकरार रखा जाएगा या नहीं। एन.एच.आर.सी. की संरचना



मानवाधिकार जांच में पुलिसकर्मियों की उपस्थिति, लिंग और अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व की कमी को लेकर चिंताओं के कारण साल 2023 में इसकी रेटिंग रोक दी गई थी। रिपोर्ट में कहा है कि अब इस पर चर्चा होनी है कि भारतीय मानवाधिकार आयोग को ए या बी रेटिंग दी जाए।

## 1 मई को होगी बैठक

आधिकारिक सूत्रों के हवाले से

रिपोर्ट में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र की मान्यता प्राप्त ग्लोबल अलायंस ऑफ नैशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस (जी.ए.एन.एच.आर.आई.) की मान्यता पर सब-कमेटी (एस.सी.ए.) की बैठक 1 मई को होगी, जो पांच साल में एक बार होने वाले रिव्यू का हिस्सा है।

संस्था के 114 सदस्य देशों के लिए ये रिव्यू किया जाता है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि विदेश मंत्रालय ने राजनयिक चैनलों के माध्यम से समीक्षा प्रक्रिया में शामिल कई देशों से संपर्क किया है।

## 2016 में भी स्थगित हुई थी रेटिंग

यह दूसरी बार है जब मोदी सरकार को इस लिस्टिंग डाऊनग्रेड

की आशंकाओं का सामना करना पड़ रहा है। साल 1999 में मान्यता प्राप्त होने के बाद से भारत ने 2006 और 2011 में अपनी ए रेटिंग बरकरार रखी थी। साल 2016 में इसकी स्थिति स्थगित कर दी गई थी और एक साल बाद बहाल कर दी गई थी।

मार्च 2023 में एस.सी.ए. ने छह प्वाइंट वाला जो सन्निशान दिया था उसमें कहा गया था कि भारतीय मानवाधिकार आयोग सरकारी हस्तक्षेप के कारण स्वतंत्र रूप से काम करने में सक्षम होने के लिए जरूरी स्थितियां बनाने में फेल रहा है। रिपोर्ट में आयोग की जांच प्रक्रिया में पुलिस अधिकारियों की भागीदारी के लिए भारत की आलोचना की थी और इसे हितों का टकराव बताया गया था।

# भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रेटिंग बहाली को लेकर संयुक्त राष्ट्र ले सकता है फैसला

जालंधर, 29 अप्रैल (इंट): संयुक्त राष्ट्र की जेनेवा में होने वाली एक बैठक में भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) के मौजूदा स्टेटस को बरकरार रखने को लेकर फैसला हो सकता है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस सप्ताह जेनेवा में होने वाली एक बैठक में आयोग सरकार की मानवाधिकार प्रक्रियाओं का बचाव करने की तैयारी कर रहा है।

### 2023 में रोक दी गई थी रेटिंग

इस बैठक में इस बात का फैसला होने की उम्मीद है कि भारत का मानवाधिकार आयोग का वर्तमान "ए स्टेटस" बरकरार रखा जाएगा या नहीं। एन.एच.आर.सी. की संरचना



मानवाधिकार जांच में पुलिसकर्मियों की उपस्थिति, लिंग और अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व की कमी को लेकर चिंताओं के कारण साल 2023 में इसकी रेटिंग रोक दी गई थी। रिपोर्ट में कहा है कि अब इस पर चर्चा होनी है कि भारतीय मानवाधिकार आयोग को ए या बी रेटिंग दी जाए।

**1 मई को होगी बैठक**  
आधिकारिक सूत्रों के हवाले से

रिपोर्ट में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र की मान्यता प्राप्त ग्लोबल अलायंस ऑफ नैशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस (जी.ए.एन.एच.आर.आई.) की मान्यता पर सब-कमेटी (एस.सी.ए.) की बैठक 1 मई को होगी, जो पांच साल में एक बार होने वाले रिव्यू का हिस्सा है।

संस्था के 114 सदस्य देशों के लिए ये रिव्यू किया जाता है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि विदेश मंत्रालय ने राजनयिक चैनलों के माध्यम से समीक्षा प्रक्रिया में शामिल कई देशों से संपर्क किया है।

2016 में भी स्थगित हुई थी रेटिंग  
यह दूसरी बार है जब मोदी सरकार को इस लिस्टिंग डाऊनग्रेड

की आशंकाओं का सामना करना पड़ रहा है। साल 1999 में मान्यता प्राप्त होने के बाद से भारत ने 2006 और 2011 में अपनी ए रेटिंग बरकरार रखी थी। साल 2016 में इसकी स्थिति स्थगित कर दी गई थी और एक साल बाद बहाल कर दी गई थी।

मार्च 2023 में एस.सी.ए. ने छह प्वाइंट वाला जो सन्निशन दिया था उसमें कहा गया था कि भारतीय मानवाधिकार आयोग सरकारी हस्तक्षेप के कारण स्वतंत्र रूप से काम करने में सक्षम होने के लिए जरूरी स्थितियां बनाने में फेल रहा है। रिपोर्ट में आयोग की जांच प्रक्रिया में पुलिस अधिकारियों की भागीदारी के लिए भारत की आलोचना की थी और इसे हितों का टकराव बताया गया था।



# भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रेटिंग बहाली को लेकर संयुक्त राष्ट्र ले सकता है फैसला

जालंधर, 29 अप्रैल (इंट): संयुक्त राष्ट्र की जेनेवा में होने वाली एक बैठक में भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) के मौजूदा स्टेटस को बरकरार रखने को लेकर फैसला हो सकता है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस सप्ताह जेनेवा में होने वाली एक बैठक में आयोग सरकार की मानवाधिकार प्रक्रियाओं का बचाव करने की तैयारी कर रहा है।

## 2023 में रोक दी गई थी रेटिंग

इस बैठक में इस बात का फैसला होने की उम्मीद है कि भारत का मानवाधिकार आयोग का वर्तमान "ए स्टेटस" बरकरार रखा जाएगा या नहीं। एन.एच.आर.सी. की संरचना



मानवाधिकार जांच में पुलिसकर्मियों की उपस्थिति, लिंग और अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व की कमी को लेकर चिंताओं के कारण साल 2023 में इसकी रेटिंग रोक दी गई थी। रिपोर्ट में कहा है कि अब इस पर चर्चा होनी है कि भारतीय मानवाधिकार आयोग को ए या बी रेटिंग दी जाए।

## 1 मई को होगी बैठक

आधिकारिक सूत्रों के हवाले से

रिपोर्ट में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र की मान्यता प्राप्त ग्लोबल अलायंस ऑफ नैशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस (जी.ए.एन.एच.आर.आई.) की मान्यता पर सब-कमेटी (एस.सी.ए.) की बैठक 1 मई को होगी, जो पांच साल में एक बार होने वाले रिव्यू का हिस्सा है।

संस्था के 114 सदस्य देशों के लिए ये रिव्यू किया जाता है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि विदेश मंत्रालय ने राजनयिक चैनलों के माध्यम से समीक्षा प्रक्रिया में शामिल कई देशों से संपर्क किया है।

## 2016 में भी स्थगित हुई थी रेटिंग

यह दूसरी बार है जब मोदी सरकार को इस लिस्टिंग डाऊनग्रेड

की आशंकाओं का सामना करना पड़ रहा है। साल 1999 में मान्यता प्राप्त होने के बाद से भारत ने 2006 और 2011 में अपनी ए रेटिंग बरकरार रखी थी। साल 2016 में इसकी स्थिति स्थगित कर दी गई थी और एक साल बाद बहाल कर दी गई थी।

मार्च 2023 में एस.सी.ए. ने छह प्वाइंट वाला जो सन्निशान दिया था उसमें कहा गया था कि भारतीय मानवाधिकार आयोग सरकारी हस्तक्षेप के कारण स्वतंत्र रूप से काम करने में सक्षम होने के लिए जरूरी स्थितियां बनाने में फेल रहा है। रिपोर्ट में आयोग की जांच प्रक्रिया में पुलिस अधिकारियों की भागीदारी के लिए भारत की आलोचना की थी और इसे हितों का टकराव बताया गया था।

## **NHRC discusses on access to legal aid to victims**

NHRC, India organised an open house discussion on 'Enhancing Access to Legal Aid for Victims.' The meeting was chaired by Chairperson, Justice Arun Kumar Mishra. In the meeting Members, Rajiv Jain and Vijaya Bharathi Sayani; Secretary General Bharat Lal; along with other officers of the Commission and the Government were present. It was also attended by representatives from various governmental ministries, autonomous bodies, legal practitioners, non-governmental organisations (NGOs), who contributed to the discussion.

## बीहर नदी में डूबे छात्रों के शव मिलने के बाद रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने दिए अधिकारियों को बड़े निर्देश

<https://www.rewariyasat.com/rewa/after-the-bodies-of-drowned-students-were-found-in-bihar-river-rewa-collector-pratibha-pal-gave-big-instructions-to-the-officials-115396>

शहर के मध्य से बहने वाली बीहर नदी के घाटों में दुर्घटना से बचाव के उद्देश्य से संकेतक लगाकर लोगों को सचेत करें। साथ ही सभी चिन्हित 10 घाटों में दुर्घटना से बचाव के उपाय सुनिश्चित कराएं। उक्त आशय के निर्देश कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने नगर निगम के अधिकारियों को दिए। उन्होंने करहिया घाट का भ्रमण किया। इस दौरान आयुक्त नगर निगम श्रीमती संस्कृति जैन भी उपस्थित रहीं।

कलेक्टर ने कहा कि गर्मी के दिनों में अक्सर नदी में लोग नहाने जाते हैं। नदी का प्रवाह अधिक होने व उसकी गहराई का अनुमान न होने से दुर्घटनाएं हो जाती हैं। इसके लिए जरूरी है कि सभी घाटों में संकेतक लगाकर लोगों को सचेत किया जाए तथा गहराई की सीमा के लिए नदी में बांस लगा दें ताकि उस क्षेत्र से आगे लोग नहाने के लिए न जाएं। उन्होंने शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में नहरों में भी दुर्घटना से बचाव के सभी उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। भ्रमण के दौरान जिला कमाण्डेंट होमगार्ड वीरेन्द्र सिंह जादौन भी उपस्थित रहे।

### राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के स्पेशल मॉनीटर ने किया वृद्धाश्रम एवं जेल का निरीक्षण

रीवा: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्पेशल मॉनीटर श्री बालकृष्ण गोयल ने अपने रीवा जिले के प्रवास के दौरान वृद्धाश्रम एवं केन्द्रीय जेल का निरीक्षण किया। स्वागत भवन स्थित वृद्धाश्रम के निरीक्षण के दौरान उन्होंने वृद्धजनों के आधार कार्ड होने तथा उन्हें मिल रही पेंशन के बारे में जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि वृद्धजनों के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएं। उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक माह वृद्धाश्रम में वृद्धजनों का स्वास्थ्य परीक्षण कराएं जिसमें आँख एवं दाँत सहित हड्डी रोग से संबंधित विशेषज्ञ अनिवार्यतः रहें। उन्होंने वृद्धजनों को परिचय पत्र उपलब्ध कराने की बात भी कही।

स्पेशल मॉनीटर ने जेल के निरीक्षण के दौरान निर्देश दिए कि कैदियों को गुणतापूर्ण भोजन उपलब्ध कराएं तथा उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं का ख्याल रखा जाए। महिला बंदियों के लिए 5 बिस्तर की चिकित्सा सुविधा के लिए व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें तथा उनके साथ रह रहे बच्चों को भी सभी सुविधाएं मिले। श्री गोयल ने निर्देश दिए कि जमानत मिलने के बाद कोई भी बंदी जेल में न रहे इस बात की सुनिश्चितता हो। उन्होंने बंदियों को जीवन कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के निर्देश भी भ्रमण के दौरान दिए।

## मानवाधिकार आयोग ने एमबीएस अस्पताल को जारी किया नोटिस

कोटा @ पत्रिका. एमबीएस अस्पताल में 17 मई 2022 को आईसीयू वार्ड में भर्ती लकवाग्रस्त महिला की दाहिनी आंख की पलक को चूहों के कुतरने के मामले में भंवरलाल की याचिका को सही मानते हुए मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव के माध्यम से पीएचआर अधिनियम की धारा 18(1)(ए) के तहत एमबीएस अस्पताल को कारण बताओ नोटिस जारी किया। इस मामले में विधि छात्र भंवरलाल सारण ने मानवाधिकार आयोग में याचिका दायर की थी। इसको 22 अप्रैल 2024 को आयोग के समक्ष रखा गया। आयोग के निर्देश पर 15 फरवरी 2024 की अनुपालना में चिकित्सा शिक्षा विभाग के उप सचिव से भी रिपोर्ट प्राप्त हुई। साथ ही, एमबीएस अस्पताल अधीक्षक की रिपोर्ट भी प्राप्त हुई है। अस्पताल की ओर से पांच सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट को रखा गया। इसमें बताया कि 17 मई 2022 को सुबह 3 बजे रोगी रूपमती की दाहिनी पलक से रक्तस्राव की घटना हुई। आयोग ने इसमें अस्पताल के कर्मचारियों की लापरवाही माना, जो मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन

हैं, जिसके लिए राज्य उत्तरदायी है। आयोग ने मुख्य सचिव को नोटिस जारी करते हुए कहा कि क्यों न आयोग राजस्थान राज्य को सरकारी कर्मचारियों की ओर से की गई लापरवाही के लिए पीड़ित के रिश्तेदार को 25 हजार का मुआवजा देने की सिफारिश करे। मुख्य सचिव को चार सप्ताह के अंदर कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के निर्देश दिए।

**NHRC holds Core Group meeting on health and mental health**

NHRC, India organised a meeting of the Core Group on Health and Mental Health issues. The meeting deliberated on the rights of patients and doctors. It was held in hybrid mode, chaired by Justice Arun Mishra, Chairperson, NHRC, in the presence of Rajiv Jain, Member, NHRC, Bharat Lal, Secretary General, and other officers. The meeting was attended by the members of the Core Group, representatives from the Government, including the Ministry of Health and Family Welfare, and other institutions.

---



## मानव अधिकारों के प्रति सचेत होकर कार्य करें: स्पेशल मानीटर गोयल

<https://www.hindusthansamachar.in/Encyc/2024/4/30/Work-with-awareness-of-human-rights-Special.php>

रीवा, 29 अप्रैल (हि.स.)। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली के स्पेशल मानीटर बालकृष्ण गोयल की अध्यक्षता में सोमवार को सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन कर मानवाधिकार, बाल संरक्षण, पोस्को एक्ट, जेजे एक्ट, वृद्ध जनों के अधिकार, जेल में निरूद्ध कैदियों के अधिकारों आदि पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में अपर कलेक्टर सपना त्रिपाठी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर, एसडीएम हुजूर वैशाली जैन सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। स्पेशल मानीटर श्री गोयल ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन तथा कार्यों के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानव अधिकारों के उल्लंघन को किसी भी स्तर पर बर्दास्त नहीं करता है। हम सभी को अपने कार्य क्षेत्र में मानव अधिकारों के संरक्षक के रूप में सचेत होकर कार्य करने की आवश्यकता है। बच्चे, बुजुर्ग एवं महिलाओं से संबंधित शिकायतें न हों तथा उनके प्रति अपराध भी न हों इस पर कड़ी नजर रखी जाय। उन्होंने कहा कि लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना हमारी जिम्मेदारी है। कई बार लोग जानकारी के अभाव में शोषण और उत्पीड़न का शिकार होते हैं। जन जागरूकता से शोषण एवं उत्पीड़न से उनका बचाव किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि पीड़ित व्यक्ति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग कर सीधे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आयोग शिकायतों को संज्ञान में लेकर तत्परता से कार्यवाही करता है।

मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशील होकर करने के लिए निर्देशित किया। स्पेशल मानीटर ने सभी विभागों को नवाचार करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंनेनेन्हों नेजिले में अनाथ बच्चियों के संरक्षण के लिये स्थल चयन के लिये प्रस्ताव प्रेषित करने के निर्देश दिये। उन्होंनेनेन्हों नेकहा कि मानव अधिकार हम सभी के जीवन में महत्वपूर्ण है। यह हमें गरिमामय जीवन जीने का अधिकार देता है। मानव अधिकारों के संरक्षण के रूप में शासकीय सेवकों तथा संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। पीड़ित के अधिकारों की रक्षा के लिए दोषियों को भी विहित प्रावधानों का पालन करते हुए सजा दी जाती है। उनके मानवाधिकार को भी ध्यान में रखा जाता है। उन्होंनेनेन्हों नेजेल में व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली तथा महिला बंदियों के लिये चिकित्सा सुविधा विस्तार के निर्देश दिये। उन्होंनेनेन्हों नेसुरक्षित स्कूल वाहन परिवहन हेतु व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। अपर कलेक्टर सपना त्रिपाठी ने आश्चस्त किया कि सभी अधिकारी मानव अधिकारों के प्रति सजग रहकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास प्रतिभा पाण्डेय, सहायक संचालक महिला बाल विकास आशीष द्विवेदी सहित प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश



## रीवा: राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के स्पेशल मॉनीटर ने किया वृद्धाश्रम एवं जेल का निरीक्षण

<https://www.hindusthansamachar.in/Encyc/2024/4/30/Rewa-Special-monitor-of-National-Human-Rights.php>

रीवा, 29 अप्रैल (हि.स.)। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्पेशल मॉनीटर बालकृष्ण गोयल ने सोमवार को अपने रीवा जिले के प्रवास के दौरान वृद्धाश्रम एवं केन्द्रीय जेल का निरीक्षण किया। स्वागत भवन स्थित वृद्धाश्रम के निरीक्षण के दौरान उन्होंने ने वृद्धजनों के आधार कार्ड होने तथा उन्हें मिल रही पेंशन के बारे में जानकारी ली। इस मौके पर उन्होंने ने निर्देश दिए कि वृद्धजनों के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएं। उन्होंने ने निर्देशित किया कि प्रत्येक माह वृद्धाश्रम में वृद्धजनों का स्वास्थ्य परीक्षण कराएं जिसमें आँख एवं दाँत सहित हड्डी रोग से संबंधित विशेषज्ञ अनिवार्यतः रहें। उन्होंने ने वृद्धजनों को परिचय पत्र उपलब्ध कराने की बात भी कही। स्पेशल मॉनीटर गोयल ने जेल के निरीक्षण के दौरान निर्देश दिए कि कैदियों को गुणत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराएं तथा उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं का ख्याल रखा जाए। महिला बंदियों के लिए 5 बिस्तर की चिकित्सा सुविधा के लिए व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें तथा उनके साथ रह रहे बच्चों को भी सभी सुविधाएं मिले। श्री गोयल ने निर्देश दिए कि जमानत मिलने के बाद कोई भी बंदी जेल में न रहे इस बात की सुनिश्चितता हो। उन्होंने ने बंदियों को जीवन कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के निर्देश भी भ्रमण के दौरान दिए। हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश

## Rehab of rape victim

# NHRC seeks report from Kendrapada admn

**RAJESH BEHERA**  
KENDRAPADA

The National Human Rights Commission (NHRC) recently directed to the district Magistrate and SP of Kendrapada to submit a report regarding compensation to be paid to a rape victim along with the proof of payment within four weeks positively.

The DM and the SP have also been directed to submit the additional/complete report in the matter latest by June 3 before the Commission.

Acting on a petition filed by a rights activist, Sagar Jena of Kendrapada, the NHRC passed the order.

The complainant brought

to the notice of the Commission alleging that a woman was raped and the act was filmed to blackmail her by the accused.

The unfortunate incident occurred in November, 2021. The accused had arranged a feast near the victim's neighbourhood during which he spiked her food and when the woman became unconscious, the accused raped her and recorded the act. After that the accused blackmailed and demanded Rs 1.5 lakh from the victim. Even, the accused threatened her and raped her multiple times. The victim on January 5, 2022 finally lodged a complaint.

Being a serious matter and

gross violation of human rights, complainant Jena had requested the Commission to intervene.

Later, the Commission sought an action taken report from the officials on 22.09.2022. Since no report was received, reminders were sent on 10.02.2023 and 16.03.2023 to the concerned authorities.

In response to the notice of the Commission, a report dated 2.5.23 was received from the SP of Kendrapada. As per the report, it was informed to the Commission that a case bearing Marshaghai PS case No-331 dated 25.8.2022 was registered under Section 323,506,376(D), 307, 34 of

IPC against four accused persons. One accused was arrested by the police on 30.8.2022 and forwarded to custody. The DSP, Kendrapada has supervised the case.

A letter was sent to the District Legal Service Authority, Kendrapada, requesting financial assistance to the victim.

Despite lapse of considerable time period, the district authorities had not submitted conclusive report with respect to the payment of the monetary compensation to the victim.

The investigation of the case was stated to be pending, but no subsequent report had been submitted on the final outcome of the case.

## **Demands for prison reforms continue as SC pulls up States for failing to follow its directives on prison reforms and providing inadequate data on prison infrastructure**

<https://cjp.org.in/demands-for-prison-reforms-continue-as-sc-pulls-up-states-for-failing-to-follow-its-directives-on-prison-reforms-and-providing-inadequate-data-on-prison-infrastructure/>

Justice Kohli observed that dingy and overcrowded prisons make prisoners more ill, and living in such conditions is not the idea of punishment

On April 23, while hearing the plea for prison reforms (W.P.(C) No. 406/2013), the Supreme Court bench of Justices Hima Kohli and Ahsanuddin Amanullah castigated the States for not providing proper details in their affidavits about the conditions of prisons, and neglecting the court directives to carry out prison reforms in district and central jails based on the recommendations of District Committees setup by the court through its order on January 30, 2024. It also expressed displeasure over the States' lackadaisical approach for not treating the matter seriously, and for failing to provide necessary information about the steps taken to improve prison infrastructure and living standards in jails.

The court gave couple of weeks' time to the Chief Secretaries of the concerned States/UTs to file the affidavits, "emphasizing that the affidavits shall mention the manner in which recommendations given by the respective Committees are proposed to be implemented and the timelines for such implementation", LiveLaw reported.

Notably, in its January order the bench had directed the States/UTs to create District Committees comprising District Judge, District Magistrate, Superintendent of Police, Secretary of District Legal Services Authority, and Superintendent of Jail, to study the conditions of prisons at a district level and send their recommendations to States for improving living conditions of prisoners, including creation of new prisons to reduce overcrowding, and ensuring proper sanitation, hygiene, food, health, education, and other services in the prisons.

In one of its earlier judgements in the same case, in February 2016, the bench of Justices Madan Lokur and R.K. Agrawal had asked States to strictly implement Model Prison Code 2016, and cautioned that it "needs to be implemented with due seriousness and dispatch" so that it is not "reduced to yet another document that might be reviewed only decades later, if at all". In the same judgement, the bench had also taken note of the plight of undertrial prisoners and had urged the States to see to it that poor undertrial prisoner who have secured bail do not languish in jails due to their poor economic status or inability to pay bail money. Emphasising on the need to improve prison conditions, the bench directed in its judgement that "The Director General of Police/Inspector General of Police in-charge of prisons should ensure that there is proper and effective utilization of available funds so that the living conditions of the

prisoners is commensurate with human dignity. This also includes the issue of their health, hygiene, food, clothing, rehabilitation etc.” The bench then had relied on landmark judgements like Sunil Batra ((1978) 4 SCC 494), Sunil Batra (II) v. Delhi Administration ((1980) 3 SCC 488), Rama Murthy v. State of Karnataka ((1997) 2 SCC 642), and T. K. Gopal v. State of Karnataka ((2000) 6 SCC 168) to argue in favour of humanitarian prison reforms.

Rama Murthy judgement specifically lists down 9 areas of immediate concern, which includes:

Over-crowding

Delay in trial

Torture and ill-treatment

Neglect of health and hygiene

Insubstantial food and inadequate clothing

Prison vices

Deficiency in communication

Streamlining of jail visits

Management of open-air prisons

Background on Prison Reforms

Since the establishment of modern prison in India by TB Macaulay in 1935, there has been numerous attempts by governments, both pre-independence and post-independence, to change the living conditions in prisons. Post-independence, Pakwasa Committee in 1949 suggested that prisoners can be used as labour for road work without any intensive supervision over them. It was from this time onwards that a system of wages for prisoners for their labour was introduced, and subsequently, certain liberal provisions were also introduced in jails manuals by which well-behaved inmates were rewarded with remission in their sentence, as per the report prepared by the Lok Sabha Secretariat on prison reforms.

The Government of India appointed the All-India Jail Manual Committee in 1957 to prepare a model prison manual following the recommendations of Dr. W.C. Reckless regarding prison reform in India, the latter being the United Nations expert on correctional work. The aforementioned committee prepared the Model Prison Manual in 1960, which became the basis for the Central Government to appoint a working group on prisons in 1972, which recommended classification of prisoners and their treatment based on certain principles.



In 1980 the Government of India set-up a Committee on Jail Reforms under the Chairmanship of Justice A. N. Mulla, which submitted its report in 1983 recommending the following measures:

Improving prison condition by making available proper food, clothing, and sanitation.

The prison staff to be properly trained and organized into different cadres, with the setting up an All-India Service called the Indian Prisons & Correctional Service.

After-care, rehabilitation and probation to be an integral part of prison service.

The press and public to be allowed inside prisons and allied correctional institutions periodically, so that the public may have first-hand information about the conditions of prisons and be willing to co-operate in rehabilitation work.

Undertrials in jails to be reduced to bare minimum and they be kept away from convicts. Furthermore, the number of undertrials to be reduced by speedy trial and liberalization of bail provisions.

The Government may make an effort to provide adequate financial resources.

Shortly afterwards in 1987, Justice Krishna Iyer Committee, setup to study the conditions of women prisoners, recommended induction of more women into the police force in view of their special role in tackling women and child offenders.

Following the Supreme Court direction in Rama Murthy (mentioned above) to prepare uniform prison laws across the country, a draft Model Prison Management Bill (The Prison Administration and Treatment of Prisoners Bill, 1998) was circulated among the States, but pertinently, the Bill was never finalised. Since then, two Model Prison Manual(s) have already come out, one in 2003, and the latest one in 2016.

In 2021, Rajya Sabha MP K.C. Ramamurthy requested the Minister of Home Affairs to provide details about the salient features of 2016 Model Prison Manual, its implementation by the States, and how the Government intends to ensure the implementation of Nelson Mandela Rules in prisons.

Responding to his query, Minister of State for Home Affairs (MoS), G. Kisan Reddy, stated the following in response to highlight the salient features of Model Prison Manual 2016:

It brings in basic uniformity in laws, rules and regulations governing the administration of prisons and the management of prisoners all over the country

Lays down the framework for both sound custody and treatment of prisoners

Spells out minimum standards of institutional services for the care, protection, treatment, education, training and re-socialisation of incarcerated offenders

Evolving procedures for the protection of human rights of prisoners within the limitations imposed by the process of incarceration

Individualises institutional treatment of prisoners in keeping with their personal characteristics, behavioural patterns and correctional requirements

Forging constructive linkages between prison programmes and community- based welfare institutions in achieving the objective of the reformation and rehabilitation of prisoners

Access to free legal services: legal aid clinics, jail visiting advocates, constitution of under-trial review committees

Provisions for women prisoners including safeguards, protections, special programmes, counselling, focussed after-care and rehabilitation, as well as provisions for children of women prisoners

Legal aid to prisoners sentenced to death, mental health evaluation, procedures and channels for mercy petition

Prison Modernisation: Use of technology/software including Personnel Information System, installation of CCTVs etc. to prevent violation of Human Rights

While commenting on the conformity to the Nelson Mandela Rules, MoS for Ministry of Home Affairs suggested that States are ultimately responsible for their implementation, and the Union Government has already sent the respective Rules to the States, asking them to implement the same. The response also noted that the Union has advised the States to have these rules (Nelson Mandela Rules) “translated in local language and disseminate the guidance contained therein to all prison officials to ensure that these rules are followed by the officials concerned in dealing with prison inmates.”

CJP’s endeavour towards bringing police accountability and prison reforms

CJP has in the past reported about the incidents affecting right to liberty of the citizens (Article 21) due to police accesses and has also advocated for the police reforms. In the case of Pankaj Kumar Sharma v Govt of NCT of Delhi & Ors, CJP reported how the Delhi High Court came down heavily on the Delhi Police personnel responsible for illegally detaining the citizen (Pankaj Kumar Sharma) and issued a compensation of 50,000 rupees from the salaries of the two police officials responsible for the misconduct, namely, (Sub-Inspectors) Rajeev Gautam and Shamim Khan. In the judgement delivered by Justice Subramonium Prasad, the court noted that “The time spent in the lock-up by the petitioner, even for a short while, cannot absolve the police officers who have deprived the petitioners of his liberty without following the due procedure established by law... This Court is of the opinion that a meaningful message must be sent to the authorities that police officers cannot be law unto themselves”.

In the aforementioned case, the court relied on number of important judicial precedents, including D K Basu v. State of West Bengal, in which the apex court had released guidelines to be followed by the police while arresting or detaining a concerned citizen.

The DK Basu guidelines among other things require the police to ensure the following:

The police personnel carrying out the arrest and handling the interrogation of the arrestee should bear accurate, visible and clear identification and name tags with their designations. The particulars of all such police personnel who handle interrogation of the arrestee must be recorded in a register

That the police officer carrying out the arrest shall prepare a memo of arrest at the time of arrest and such memo shall be attested by at least one witness, who may be either a member of the family of the arrestee or a respectable person of the locality from where the arrest is made. It shall also be counter signed by the arrestee and shall contain the time and date of arrest.

A person who has been arrested or detained and is being held in custody in a police station or interrogation centre or other lock up, shall be entitled to have one friend or relative or other person known to him or having interest in his welfare being informed, as soon as practicable, that he has been arrested and is being detained at the particular place, unless the attesting witness of the memo of arrest is himself such a friend or a relative of the arrestee.

The time, place of arrest and venue of custody of an arrestee must be notified by the police where the next friend or relative of the arrestee lives outside the district or town through the Legal Aid Organisation in the District and the police station of the area concerned telegraphically within a period of 8 to 12 hours after the arrest.

The person arrested must be made aware of his right to have someone informed of his arrest or detention as soon as he is put under arrest or is detained.

An entry must be made in the diary at the place of detention regarding the arrest of the person which shall also disclose the name of the next friend of the person who has been informed of the arrest and the names and particulars of the police officials in whose custody the arrestee is.

The arrestee should, where he so requests, be also examined at the time of his arrest and major and minor injuries, if any present on his/her body, must be recorded at that time. The 'Inspection Memo' must be signed both by the arrestee and the police officer effecting the arrest and its copy provided to the arrestee.

The arrestee should be subjected to medical examination by the trained doctor every 48 hours during his detention in custody by a doctor on the panel of approved doctors appointed by Director, Health Services of the concerned State or Union Territory, Director, Health Services should prepare such a panel for all Tehsils and Districts as well.

Copies of all the documents including the memo of arrest, referred to above, should be sent to the Magistrate for his record.

The arrestee may be permitted to meet his lawyer during interrogation, though not throughout the interrogation.

In addition, the judgement also relied on Nilabati Behera (1993 AIR 1960) to provide compensation to the victim of illegal act of detention carried out by the police. Importantly, in Nilabati Behera the court had noted that “citizen complaining of the infringement of the indefeasible right under Article 21 of the Constitution cannot be told that for the established violation of the fundamental right to life, he cannot get any relief under the public law by the courts exercising writ jurisdiction.”

Similarly, CJP continued to raise awareness about the Police Complaints Authorities (PCA) in Maharashtra, for which a user guide was initially released by the Commonwealth Human Rights Initiative (CHRI). PCAs were established in Maharashtra in 2014 at the state level (1) and divisional level (6) to register complaints or grievances against police personnel for serious misconduct, corruption, or abuse of authority.

PCAs have wide ambit of power to perform the following functions:

Conduct suo moto inquiries or through complaints against Police Officers, hear all concerned persons, receive evidence, and give recommendations to be implemented by the police department and the state government

Advise the state government to ensure the protection of witnesses, victims and their families who face, or may face, threats or harassment for filing a complaint against the police

Visit any police station, lock-up or other place of detention used by the police (with written authorisation from the Chairperson).

Receive complaints involving death in police custody, grievous hurt under Section 320 of the IPC, rape or attempt to commit rape, arrest or detention without following procedure, corruption, extortion, land or house grabbing and any other serious violation of law or abuse of authority

In 2018, CJP once again raised its voice against the growing misuse of police across the country to suppress peaceful protests by the citizens. It moved the National Human Rights Commission (NHRC) demanding guidelines on how the police should behave with peaceful protestors in order to protect citizens' right to peaceful protest under Article 19 of the Constitution.

CJP-PUCL manifesto on prison reforms and police accountability

Before the election to Lok Sabha 2024 took off, CJP and PUCL jointly released their manifesto, which among other things also deal with the long pending issue of prison reforms, especially with regard to the rights of undertrial prisoners. The following demands have been raised in our manifesto:

Follow and implement relevant judgments of the Supreme Court on under trials and ensure prison reforms in accordance with the Model Manual for Prison Reform, 2016.



Order the immediate release of under trials who have already served half their maximum sentence.

Ensure regular monitoring of prison conditions, particularly in relation to women and children through the implementation of district and other monitoring committees as per the Model Manual Prison Reform, 2016.

Ensure adequate sanitation and health facilities, and emphasise cleanliness and adequate food and clean water; access to work, reading and writing materials in all prisons.

Ensure efficient, regular and quality legal aid to all under trials and other prisoners.

Ensure the emoluments to the prison employment staff (including services of convicted prisoners utilised by the state) meet the standards of the updated standards in the Minimum Wages Act, 1948.

Ensure training and sensitisation of all Jail/Prison staff in national and international human rights standards to ensure just and humane conditions within prisons.

Explore the shift to an Open Prison System for less stringent crimes.

Allow human rights defenders (HRDs) full and free access to police stations, prisoners, etc.

Abolition of capital punishment and all forms of torture.

Ratification of the United Nations Convention Against Torture (UNCAT), effecting of changes in domestic legislation to ensure compliance with the provisions of UNCAT and introduction of domestic law against torture and ill-treatment in line with the provisions of UNCAT.

Ensure the strictest adherence to the rule of law and immediately put a stop to all forms of torture by the police, custodial killings, extra judicial / encounter killings etc.

Remove requirement for sanction to prosecute police officers, military personnel and public officials from all laws and take strictest action against erring officers.

Strengthen the law already enacted for the protection of whistle blowers.

Full implementation of police reform provisions in line with not just the Supreme Court judgement in the Prakash Singh case, but also the recommendations made by the National Police Commission Reports.

Ensure the establishment of Independent Directorates of Prosecutions that are monitored by the higher judiciary and are independent of the executive arm of the government. Image Courtesy: etvbharat.com

## **India's Human Rights accreditation Status under Review by Geneva-based UN body**

<https://english.varthabharati.in/india/indias-human-rights-accreditation-status-under-review-by-geneva-based-un-body>

Geneva: India's human rights accreditation status is under scrutiny as the Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI) prepares to review the country's processes this week. The National Human Rights Commission (NHRC) faces potential downgrading from its current "A status" due to concerns raised in 2023, including the lack of pluralism, the appointment of police officials and ruling party members to the NHRC, and the absence of gender and minority representation.

The decision on India's accreditation status will impact its ability to vote at the UN Human Rights Council and some UNGA bodies. The Sub-Committee on Accreditation (SCA) of GANHRI will conduct the review, which occurs every five years for each member of the 114-member alliance. India, which has been accredited since 1999, had its status deferred in 2016 but restored after a year.

The NHRC has defended its composition, stating that the presence of government officials, including the Secretary-General and CEO, enhances its effectiveness. However, criticisms include the involvement of police officers in investigations, lack of gender and minority representation, and political affiliations of some members with the ruling party.

The Ministry of External Affairs (MEA) has engaged with countries involved in the review process to present India's case diplomatically. Despite confidence in restoring its A status, the government emphasizes that it does not focus on "external certifications" of India's human rights record.

International civil society organizations, including Amnesty International, Human Rights Watch, and CIVICUS, have raised concerns about increasing restrictions on civil society and discrimination against minorities in India. They urge GANHRI-SCA to amend the NHRC's rating to reflect its failure to comply with the Paris Principles and address the deteriorating human rights situation in India.

The Ministry of External Affairs has criticized the U.S. State Department's latest human rights report on India as biased and reflective of a poor understanding of the country. It further stated that it attaches no value to the report and urges others to do the same.